Rajasthali Law Institute

Prelims test series

CRPC PAPER-7

(Chapter 31 to 37)

1)मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है**?(U.P. A.P.O. (Spl.) 2007 M.P. (CJ) 2001)**

(a) संबंधित उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार

(b) भारत का महान्यायवादी

(c) भारतीय विधिज्ञ परिषद का अध्यक्ष

(d) भारत का महा-सालिसिटर

1)The power of the Supreme Court to transfer cases and appeals from one High Court to another can be exercised on the application of which one of the following?

(a) Registrar of the concerned High Court

(b) Attorney General of India

(c) President of the Bar Council of India
(d) Solicitor General of India

2)यदि कोई अभियुक्त जिसका विचारण नागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहा है. अपना मामला पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानान्तरित कराना चाहता है तब उसे आवेदन देना होगा**(M.P.A.P.O.1995)**
(a) नागपुर के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में
(b) पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में
(c) दोनी राज्यों के उच्च न्यायालयों में
(d) भारत के उच्चतम न्यायालय में

2) If any accused whose trial is going on in the Judicial Magistrate Court at Nagpur. If he wants to get his case transferred to the Magistrate's Court of Patna then he will have to apply.
(a) In the Court of Magistrate's of Nagpur
(b) In the Court of Magistrate of Patna
(c) In the High Courts of both the states
(d) In the Supreme Court of India

3)प्रतिशोध का सिद्धांत**-(U.P. H.JS. 2012)**

(a) एक सिद्धांत है जिसमें अपराधी को अनुकरणीय सजा दी जाएगी
(b) एक सिद्धांत है कि अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए
(c) एक सिद्धांत है जिसमें अपराधी को सुधारा जाना चाहिए
(d) एक सिद्धांत है जिसमें अपराधी को खुली जेल में भेजा जाना चाहिए

3)Theory of retribution-
(a) Is a theory in which exemplary punishment shall be given to criminal
(b) Is a theory that a criminal should be punished in proportion to his offence
(c) Is a theory in which the criminal must be reformed
(d) Is a theory in which criminal should be sent to open jail

4)दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की किस धारा में वादों और अपीलों को अन्तरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्ति का है।**(UP.AP.O. 2007)**

(a) धारा 409
(b) धारा 408
(c) धारा 407
(d) धारा 406

4) Which section of the Code of Criminal Procedure, 1973 provides for the power of the Sessions Judge to transfer cases and appeals?
(a) Section 409
(b) Section 408
(c) Section 407
(d) Section 406

5)दण्ड प्रक्रिया संहिता में मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है**?(M.P.A.P.O. 2009)**
(a) भारत का सॉलिसिटर जनरल
(b) भारत का न्यायवादी
(c) हितबद्ध पक्षकार
(d) या तो (b) अथवा (c) दोनों के

5)Under the Code of Criminal Procedure, the power of the Supreme Court to transfer cases and appeals from one High Court to another can be exercised on the application of which of the following?

(a) Solicitor General of India
(b) Attorney General of India
(c) Interested parties
(d) Either (b) or (c) both

6)दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **407** संबंधित है**-(Raj. J.L.O. 2014)**

(a) मामलों एवं अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति
(b) मामलों एवं अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति
(c) मामलों एवं अपीलों को अन्तरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति
(d) उपरोक्त सभी

6) Section 407 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is related -

(a) Power of the Supreme Court to transfer cases and appeals
(b) Power of the High Court to transfer cases and appeals
(c) Power of the Sessions Court to transfer cases and appeals
(d) All of the above

7) उच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा **407** के तहत मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है यदि **-(Bihar H.J.S. 2019)**
(a) निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच या परीक्षण संभव नहीं है
(b) मामले से परिचित एक अजनबी एक आवेदन करता है
(c) यह न्याय के उद्देश्य के लिए समीचीन है
(d) यह पार्टियों या गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए होगा।

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

7) The High Court cannot exercise the power under Section 407 of the Code of Criminal Procedure to transfer cases and appeals if -

(a) A fair and impartial inquiry or trial is not possible
(b) A stranger to the case makes an application
(c) It is expedient for the ends of justice
(d) It will tend to the general convenience of the parties or witnesses.

8)जिस स्त्री को मृत्युदण्ड दिया गया है यदि यह स्त्री गर्भवती है तो उब न्यायालय, उचित समझे तो**-(M.P. (CJ) 1993)**
(a) दण्ड आजीवन कारावास में बदल सकता है
(b) दण्ड के निष्पादन का आदेश दे सकता है
(c) बच्चे के जन्म के पश्चात् मामले को पुनः सुन सकता है
(d) राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि दण्ड का निष्पादन मुल्तवी किया जाए

8) If the woman who has been awarded death sentence is pregnant, then the court, if it deems fit -
(a) The punishment can be converted into life imprisonment
(b) Can order execution of punishment

(c) Can hear the case again after the birth of the child
(d) Can recommend to the President that the execution of the sentence be postponed

9)मृत्यु दंड को निष्पादन को मुल्तवी करने की शक्ति प्रदत्त है:**(Uttarakhand (CJ) 2019)**
(a) सत्र न्यायालय को
(b) न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को
(c) उच्च न्यायालय को
(d) जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय को

9)The power to postpone the execution of death sentence is given to:
(a) To the Sessions Court
(b) To the Court of Judicial Magistrate
(c) To the High Court
(d) To the District Magistrate's Court

10). दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी दण्डादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारन्ट जारी किया जा सकता है**-(M.P.A.P.O. 2009)**
(a) न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा

(b) पद-उत्तरवर्ती द्वारा
(c) या तो उस न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट जिसने दण्डादेश पारित किया है या उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा
(d) उपर्युक्त सभी

10). Under the Code of Criminal Procedure, every warrant for the execution of any sentence can be issued -
(a) By a judge or magistrate
(b) By successor in office
(c) Either by the Judge or Magistrate who passed the sentence or by his successor in office;
(d) All of the above

11)दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण कौन कर सकता है?**(M.P. A.P.O. 2008 U.P. A.P.O. 2002, 2007)**
(a) समुचित सरकार
(b) भारत का राष्ट्रपति
(c) राज्य का राज्यपाल
(d) केन्द्रीय सरकार

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

11) Who can commute the sentence of life imprisonment under the Code of Criminal Procedure?

(a) Appropriate government
(b) President of India
(c) Governor of the state
(d) Central Government

12). आजीवन कारावास के दण्डादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी**?(Chhattisgarh (CJ) 2003)**

(a) 20 वर्ष
(b) 18 वर्ष
(c) 14 वर्ष
(d) 12 वर्ष

12) How many years of imprisonment will the government be able to reduce the sentence of life imprisonment?

(a) 20 years
(b) 18 years
(c) 14 years
(d) 12 years

13)किसी अभियुक्त की मृत्यु दण्ड के कारावास की सजा को समुचित सरकार के द्वारा केवल जुर्माने में भी लघुकरण किया जा सकता है। यह किस विधि के प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है**?(Raj. A.P.O. 2011)**
(a) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 54 के अनुसार।
(b) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 व 161 के अनुसार।
(c) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 53 व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433(क) के अनुसारा
(d) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के अनुसार।

13) The sentence of imprisonment of an accused punishable with death can also be commuted by the appropriate Government by mere fine only This can be done according to the provision of which law?
(a) According to Section 54 of the Indian Penal Code 1860.
(b) According to Articles 72 and 161 of the Indian Constitution.
(c) According to Section 53 of the Indian Penal Code 1860 and Section 433(a) of the Code of Criminal Procedure 1973

(d) According to Section 432 of the Code of Criminal Procedure 1973.

14)मृत्यु दण्डादेश की दशा में, निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति निहित है:**(M.P.A.P.O. 2009)**
(a) राज्य सरकार में
(b) केन्द्र सरकार में
(c) राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों में
(d) राष्ट्रपति में

14) In the case of a sentence of death, the power of suspension, remission or commutation vests:
(a) In the state government
(b) In the Central Government
(c) In both state and central government
(d) In the President

15)"समुचित सरकार**"** एक अभियुक्त की मृत्युदण्ड की सजा का किसी अन्य सजा (दण्ड) में लघुकरण कर सकती है**-(Uttarakhand (CJ) 2014)**
(a) अभियुक्त की सहमति से
(b) अभियुक्त के रिश्तेदारों की सहमति से

(c) अभियुक्त के अधिवक्ता की सहमति से
(d) बिना अभियुक्त की सहमति से

15)The "appropriate Government" may commute the death sentence of an accused to any other punishment -
(a) with the consent of the accused
(b) With the consent of the relatives of the accused
(c) With the consent of the advocate of the accused
(d) without the consent of the accused

16)'अ' को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाकर, चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया। 'अ' उसी मजिस्ट्रेट से अपनी सजा निलम्बित करने हेतु आवेदन द्वारा निवेदन करता है। उस मजिस्ट्रेट को तब निम्न में से कौन-सी कार्यवाही अपनानी होगी?**(M.P. A.P.O.1995)**
(a) अधिकारिता का अभाव होने से आवेदन का निरस्तीकरण
(b) यदि वह उचित समझता है तब उसे मंजूर करना

(c) यदि अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर था तब उसका आवेदन स्वीकार करना
(d) सत्र न्यायालय को वह आवेदन अग्रेषित करना

16) 'A' was convicted by the Court of the Chief Judicial Magistrate and sentenced to four years of rigorous imprisonment. 'A' requests the same magistrate by application to suspend his sentence. Which of the following actions should the Magistrate then take?
(a) Rejection of application due to lack of jurisdiction
(b) To approve it if he thinks it appropriate
(c) To accept the application of the accused if he was on bail during the trial.
(d) Forwarding the application to the Court of Session

17)धारा **428** दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, निम्न में से भोगी गई निरोध की किस अवधि को, उस मामले में कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा**?(Raj. (CJ) 2016**
U.P.H.J.S. (P-II) 2018)

(a) जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम में भोगी गई निरोध अवधि को
(b) उस मामले के अन्वेषण व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को
(c) सदृश्य मामले के अन्वेषण व विधारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को
(d) उपरोक्त सभी को

17)Under Section 428 of the Code of Criminal Procedure, which of the following periods of detention will be set off against the sentence of imprisonment in that case?
(a) The period of detention served in default in payment of fine
(b) The period of detention suffered during the investigation and trial of that case.
(c) The period of detention suffered during the investigation and trial of a similar case.
(d) All of the above

18)'अ**'** चोरी का एक अभियुक्त था। अपनी गिरफ्तारी के बाद वह नब्बे दिवस तक निरोध में रहा। उसके पश्चात् वह

360 दिवस के कारावास भुगतने की सजा से दण्डित हुआ। क्या वह मुजराई का हकदार होगा?**(M.P. A.P.O. 1995)**
(a) नहीं
(b) हां, पूरे 90 दिन की
(c) हां. परंतु केवल 30 दिन की
(d) हां, परन्तु केवल 45 दिन की

18)'A' was an accused of theft. After his arrest he remained in detention for ninety days. After that he was sentenced to undergo imprisonment for 360 days. Will he be entitled to set-off?
(a) No
(b) Yes, for full 90 days
(c) Yes. but only for 30 days
(d) Yes, but only for 45 days

19)धारा **428** के अंतर्गत दोषसिद्धि द्वारा बताई गई निम्नलिखित निरोधावधि मुजरा नहीं हो सकती है:**(M.P. (CJ) 2010)**
(a) अन्वेषण
(b) विचारण

(c) जांच
(d) अन्य प्रकरण

19)The following period of detention prescribed by conviction under section 428 cannot be set off:
(a) Child
(b) Trial
(c) Investigation
(d) Other cases

20)गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?**(U.P. A.P.O. 2007)**
(a) यदि संबंधित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजक अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है, जमानत दी जा सकती है
(b) यदि न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व में होते हुए भी, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए ऐसे व्यक्ति को जमानत पर मुक्त करने की आवश्यकता है, जमानत दी जा सकती है

(c) ऐसे अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसकी आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचानने के लिए हो सकती है
(d) यदि अपराध मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास, अथवा सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय है, तो कोई भी व्यक्ति लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता

20)Which of the following is not correct regarding the provisions of bail in case of non-bailable offences?
(a) If the concerned court comes to the conclusion that the prosecutor has failed to establish a prima facie case against the accused, bail may be granted
(b) If the court is satisfied that despite the existence of a prima facie case, keeping in view the facts and circumstances of the case, there is a need to release such person on bail, bail can be granted.
(c) An accused who may be required for identification by witnesses in the investigation cannot be released on bail.

(d) If the offence is punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for seven years or more, no person shall be released on bail without giving the Public Prosecutor an opportunity of being heard.

21) धारा **436-A** दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** संबंधित है**(Raj. J.L.O. 2014)**
(a) अजमानतीय अपराध के मामले में जमानत
(b) अग्रिम जमानत
(c) विचाराधीन कैदी को निरुद्ध रखने की अवधि
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

21) Section 436-A of the Code of Criminal Procedure 1973 is related to
(a) Bail in case of non-bailable offence.
(b) Anticipatory bail
(c) Period of detention of the undertrial prisoner
(d) None of the above

22). समुचित सरकार किसी अभियुक्त की सजा के दण्डादेश का बिना उसकी सहमति के भी लघुकरण कर

सकती है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की**-(Uttarakhand (CJ) 2016)**

(a) धारा 432 में

(b) धारा 433 में

(c) धारा 320 में

(d) धारा 321 में

22). The appropriate government can commute the sentence of an accused even without his consent, under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 -

(a) In section 432

(b) In section 433

(c) Section 320

(d) In section 321

23)जमानती अपराध में, जमानत एक अधिकार के रूप में दी जाती है**:(U.P.H.J.S. 2018)**

(a) पुलिस अधिकारी द्वारा

(b) न्यायालय द्वारा

(c) पुलिस अधिकारी व न्यायालय दोनों द्वारा

(d) (a) या (b) द्वारा

23)In a bailable offence, bail is given as a right:

(a) By the police officer

(b) By the court

(c) By both the police officer and the court

(d) By (a) or (b)

24). कथन **(A)** दं.प्र.सं. की धारा **433** समुचित सरकार को दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति प्रदान करती

कारण **(R):** सरकार को आजीवन कारावास के दण्डादेश को दस वर्ष के कारावास के दण्डादेश में लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।

नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर संकेतित कीजिए:

(a) (A) और (R) दोनों सही है तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(b) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

U.P.A.P.O. (Spl) 2007

24). Statement (A) Section 433 of CRPC provides to the appropriate government the power to commute the sentence.
Reason (R): The Government has the power to commute the sentence of life imprisonment to ten years imprisonment.
Indicate the correct answer from the codes given below:
(a) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
(b) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
(c) (A) is correct, but (R) is wrong.
(d) (A) is wrong, but (R) is correct.

25)निम्नलिखित में से कौन वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है**?(U.P. A.P.O. 2007)**
(a) डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरन
(b) तामा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
(c) दिनेश डालमिया बनाम सी.बी.आई.
(d) डिम्पल गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता

25)Which of the following case is related to anticipatory bail?

(a) D.K. Ganesh Babu vs P.T. Manokaran

(b) Tama vs. State of West Bengal

(c) Dinesh Dalmia vs. CBI.

(d) Dimple Gupta vs Rajeev Gupta

26)किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका करने व व्यक्ति के आवेदन पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय धारा **438** दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह निर्देश दे सकता है कि**-(Chhattisgarh (CJ) 2003, 2007**
M.P. (CJ) 1996)

(a) उसको आगामी आदेश तक गिरफ्तार न किया जाए

(b) उसको अभिरक्षा में बिना लाए जमानत पर छोड़ दिया जाए

(c) ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये

(d) ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको तीन दिन पश्चात् जमानत पर छोड़ दिया जाए

26) On the application of person suspecting arrest in the case of commission of a

non-bailable offence the High Court or the Sessions Court under Section 438 Crpc it may direct that

(a) He should not be arrested till further orders

(b) He should be released on bail without bringing him into custody.

(c) In case of such arrest, he should be released on bail.

(d) In case of such arrest, he should be released on bail after three days.

27)दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **438** के तहत अग्रिम जमानत दी जा सकती है**?(M.P. (CJ) (S-II) 2019)**

(a) जमानतीय अपराधों में

(b) अजमानतीय अपराधों में

(c) जमानतीय अपराधों एवं अजमानतीय अपराधों दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

27)Can anticipatory bail be granted under section 438 of the Code of Criminal Procedure?

(a) In bailable offences

(b) In non-bailable offences

(c) Both bailable offences and non-bailable offences.
(d) none of these

28)अग्रिम जमानत' मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है**-(U.P.A.P.O. 2015 Uttarakhand (CJ) 2011, 2012 U.P. (CJ) 2012)**
(a) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में
(b) केवल सत्र न्यायालय में
(c) केवल उच्च न्यायालय में
(d) (b) तथा (c) दोनों

28)Jurisdiction to grant 'anticipatory bail' lies with-
(a) In the Chief Judicial Magistrate
(b) Only in the Sessions Court
(c) Only in the High Court
(d) (b) and (c) both

29)दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन**-**सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को अजमानतीय वाद में जमानत पर रिहा कर सकता है**?(Raj. A.P.O. 2015 Bihar (CJ) 2009)**

(a) धारा 336
(b) धारा 337
(c) धारा 436
(d) धारा437

29)Under which section of the Code of Criminal Procedure can a police officer release an accused on bail in a non-bailable case?
(a) Section 336
(b) Section 337
(c) Section 436
(d) Section 437

30)क्या विचारण की समाप्ति एवं अपील के निस्तारण के पूर्व उच्तर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए अभियुक्त से जमानत प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है**?(M.P. H.J.S. 2016)**
(a) हां, धारा 437 क दं.प्र.सं. के अनुसार
(b) हां, धारा 439 उपधारा 2क दं.प्र.सं.
(c) हां, धारा 436 दं.प्र.सं.
(d) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

30) Can the accused be asked to furnish surety to appear before the Higher Court before the end of the trial and disposal of the appeal?

(a) Yes,According to section 437 of Crpc

(b) Yes,According to section 439 sub-section 2A of Crpc

(c) Yes,According to Section 436 of Crpc

(d) There is no such provision

31)निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि "जहां यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है, गैर-जमानतीय अपराधों के अन्य सभी नामर्ता में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा"**?(U.P.A.P.O. 2011)**

(a) अफजल खान बनाम गुजरात राज्य

(b) गुरचरन सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)

(c) चन्द्रा स्वामी बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन

(d) गुरबक्श सिंह बनाम पंजाब राज्य

31) In which of the following cases, the Supreme Court held that "Where there is reasonable cause to believe that the accused is guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life, the judicial discretion in all other cases of non-bailable offences" Will be used by the court in favor of granting bail?

(a) Afzal Khan vs. State of Gujarat
(b) Gurcharan Singh vs. State (Delhi Administration)
(c) Chandra Swamy vs Central Bureau of Investigation
(d) Gurbaksh Singh vs. State of Punjab

32)जमानत हेतु अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा से संबंधित प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** में प्रदान किये गए हैं**-(Uttarakhand (CJ) 2016)**

(a) धारा 436 में
(b) धारा 436 क में
(c) धारा 437 क में
(d) धारा 438 में

32)Provisions related to the requirement of the accused to appear before the Higher Appellate Court for bail are provided in the Code of Criminal Procedure, 1973 -

(a) In section 436

(b) Section 436A

(c) Section 437A

(d) In section 438

33)दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **437**क के अनुसार, अभियुक्त द्वारा निष्पादित बंधपत्र प्रवृत्त रहेगा**-(M.P.H.J.S. 2019)**

(a) 2 माह तक

(b) 3 माह तक

(c) 4 माह तक

(d) 6 माह तक

33) According to section 437A of the Code of Criminal Procedure, the bond executed by the accused will remain in force -

(a) up to 2 months

(b) up to 3 months

(c) up to 4 months

(d) up to 6 months

34)क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपान्तरित की जा सकती है**?** यदि हां तो किसके द्वारा एवं किस प्रावधान के तहत **?(Jharkhand (CJ) 2008 U.P. A.P.O. 2007 Chhattisgarh (CJ) 2003)**

(a) उच्च न्यायालय द्वारा 482 दं.प्र.सं. के तहत

(b) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत

(c) सत्र न्यायालय द्वारा 465 दं.प्र.सं. के तहत

(d) किसी न्यायालय द्वारा ऐसी शर्तों को अपास्त या उपान्तरित नहीं किया जा सकेगा

34) Can any condition imposed by a Magistrate at the time of releasing a person on bail be set aside or modified? If yes then by whom and under which provision?

(a) By the High Court According to section 482 Code of Criminal Procedure

(b) By the High Court or Sessions Court under section 439 Code of Criminal Procedure
(c) By the Sessions Court According to section 465 Code of Criminal Procedure
(d) Such conditions cannot be set aside or modified by any court.

35)किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और उससे पर्याप्त प्रतिभू पेश करने की अपेक्षा कर सकता है**?(Raj(JS) 2019)**
(a) धारा 440 दंड प्रक्रिया संहिता।
(b) धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता।
(c) धारा 441 दंड प्रक्रिया संहिता।
(d) धारा 443 दंड प्रक्रिया संहिता।

35)Under which provision can the court issue an arrest warrant against a person released on bail and require him to produce adequate surety?
(a) Section 440 Code of Criminal Procedure.
(b) Section 446 Code of Criminal Procedure.
(c) Section 441 Code of Criminal Procedure.

(d) Section 443 Code of Criminal Procedure.

36)निम्न में से कौन-सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है?**(U.P.A.P.O. 2011)**
(a) हरियाणा राज्य बनाम जयसिंह
(b) गजानन्द अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य
(c) कल्याण चन्द्र सरकार बनाम राजेश रंजन
(d) जोगिन्दर उर्फ जिन्दी बनाम हरियाणा राज्य

36)Which of the following cases is related to anticipatory bail?
(a) State of Haryana vs. Jaisingh
(b) Gajanand Aggarwal vs. State of Orissa
(c) Kalyan Chandra Sarkar vs Rajesh Ranjan
(d) Joginder alias Jindi vs. State of Haryana

37)निम्नलिखित में से दण्ड प्रक्रिया संहिता का कौन-सा उपबन्ध अपील से संबंधित नहीं है?**(Chhattisgarh (CJ) 2007**
M.P.A.P.O. 2009)
(a) धारा 86
(b) धारा 449
(c) धारा 150

(d) धारा 454

37)Which of the following provisions of the Code of Criminal Procedure is not related to appeal?

(a) Section 86
(b) Section 449
(c) Section 150
(d) Section 454

38). दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया व्यतिक्रम निम्न में से किस कार्य को शून्यता देगा**?(M.P.A.P.O. 2009)**

(a) धारा 94 के अंतर्गत जारी किया गया तलाशी वारण्ट
(b) धारा 155 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को किसी अपराध का अन्वेषण करने का आदेश
(c) धारा 83 के अंतर्गत किसी सम्पत्ति की कुर्की या बिक्री
(d) धारा 306 के अंतर्गत साक्ष्य प्राप्त करने हेतु सह-अपराधी को दी गई माफी

38).Under the Code of Criminal Procedure, default by a competent magistrate will render which of the following acts void?

(a) Search warrant issued under section 94

(b) Order to police officer to investigate any crime under section 155
(c) Attachment or sale of any property under section 83
(d) Pardon given to accomplice for obtaining evidence under section 306

39)धारा **446** दं.प्र.सं. के अंतर्गत जमानतदार से पेनाल्टी की राशि वसूल न किए जाने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा उसे दिया जा सकने वाला कारावास है**-(M.P. H.J.S. 2016)**
(a) सिविल जेल जो छः माह तक हो सकती है।
(b) साधारण कारावास जिसकी अवधि छः माह तक हो सकती है।
(c) कठोर कारावास जिसकी अवधि छः माह तक हो सकती है।
(d) सिविल जेल जो एक वर्ष तक हो सकती है।

39)Under Section 446 of Crpc, in case the penalty amount is not recovered from the surety, the imprisonment that can be given to him by the court is-

(a) Civil jail which may extend to six months.
(b) Simple imprisonment for a term which may extend to six months.
(c) Rigorous imprisonment for a term which may extend to six months.
(d) Civil imprisonment which may extend to one year.

40)मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन-सी अनियमितताएं, जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त नहीं है, कार्यवाही को दूषित नहीं करती है**-(Raj. (CJ) 2015)**
(a) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना
b) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान लेना
(c) अपील का निर्णय करना
(d) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 466 के अंतर्गत पारित आदेश का पुनरीक्षण करना

40)Which of the following irregularities committed by a Magistrate, for which he is not

empowered by law, does not vitiate the proceedings -

(a) Calling for records to exercise the powers of revision under Section 397 of the Code of Criminal Procedure

b) Clause of sub-section (1) of section 190 of the Code of Criminal Procedure

Cognizance of any offence under clause (a) or clause (b).

(c) Deciding the appeal

(d) To review the order passed under section 446 of the Code of Criminal Procedure

41). प्रतिभूति पत्र के जब्त होने के पहले यदि प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सम्पदा पर उत्तरदायित्व**(M.P. (CJ) 2007)**

(a) समाप्त नहीं होगा

(b) समाप्त हो जाएगा

(c) न्यायालय को किसी प्रभाग का परिहार करने का विवेकाधिकार है

(d) इस हेतु कोई उपबन्ध नहीं है

41).If the surety dies before the surety bond is forfeited, liability on his estate

(a) will not end

(b) will end

(c) The court has the discretion to avoid any division

(d) There is no provision for this

42)विचारण के दौरान संपत्ति का व्ययन किस धारा में है**?(M.P.A.D.P.O. 2015)**

(a) धारा 454 दण्ड प्रक्रिया संहिता

(b) धारा 452 दण्ड प्रक्रिया संहिता

(c) धारा 453 दण्ड प्रक्रिया संहिता

(d) धारा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता

42) Under which section is the disposal of property during trial?

(a) Section 454 Code of Criminal Procedure

(b) Section 452 Code of Criminal Procedure

(c) Section 453 Code of Criminal Procedure

(d) Section 451 Code of Criminal Procedure

43)दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, **2005** द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **459** में 'दस रुपये से कम' शब्दों को किन शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है:**(U.P. A.P.O. 2005, 2007)**

(a) पांच सौ रुपये से कम
(b) पचास रुपये से कम
(c) एक सौ रुपये से कम
(d) दो सौ पचास रुपये से कम

43)Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005 In Section 459 of the Code of Criminal Procedure, the words 'less than ten rupees' have been replaced by which words:

(a) less than five hundred rupees
(b) less than fifty rupees
(c) less than one hundred rupees
(d) less than two hundred rupees

44) दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** की धारा **460** के अंतर्गत कौन-सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करती?**(Raj. J.L.O. 2014)**

(a) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करना।
(b) सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्ण आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना।
(c) भरण-पोषण के लिए आदेश देना।
(d) धारा 94 के अधीन तलाशी वारण्ट जारी करना।

44) Which irregularity does not vitiate the proceedings under Section 460 of the Code of Criminal Procedure 1973?
(a) To demand security for maintaining peace.
(b) discharges a person lawfully bound to be of good behaviour
(c) To make orders for maintenance.
(d) Issuance of search warrant under section 94.

45)निम्नलिखित में से किस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी **?(Uttaranchal (CJ) 2005 Chhattisgarh (CJ) 2007)**
(a) भरण-पोषण के लिए आदेश देना
(b) सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना
(c) सहअपराधी को क्षमादान करना

(d) किसी अपराधी का संक्षेपतः विचारण करना

45)In which of the following cases will the irregularity committed by the Magistrate not vitiate the proceedings?

(a) To give orders for maintenance

(b) To demand security for good conduct

(c) Granting pardon to an accomplice

(d) To try a offender summarily

46)दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की निम्न किस धारा के अंतर्गत वे अनियमितताएं, जो प्रक्रिया को दूषित नहीं करती हों, बताई गई हैं**-(U.P. (CJ) 2015)**

(a) धारा 460 में

(b) धारा 461 में

(c) धारा 462 में

(d) धारा 466 में

46) Under which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973, those irregularities which do not vitiate the process have been mentioned -

(a) In section 460

(b) In section 461

(c) In section 462
(d) In section 466

47)मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन-सी अनियमितता, जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त नहीं है, कार्यवाही को दूषित करती है**?(Raj. (CJ) 2015 U.P.H.J.S. (P-III) 2018 U.P.H.J.S. (P-II) 2018)**
(a) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत की गई जांच
(b) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 की उपधारा (2) के अधीन किसी मामले को हवाले करना
(c) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान करना
(d) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अधीन सह-अपराधी को क्षमादान करना।

47)Which of the following irregularities committed by a Magistrate, for which he is not empowered by law, vitiates the proceedings?
(a) Conducted Inquest under section 176 of the Code of Criminal Procedure
(b) Make over a case under sub-section (2) of section 192 of the Code of Criminal Procedure

(c) Taking cognizance of any offence under clause (c) of sub-section (1) of section 190 of the Code of Criminal Procedure
(d) To tender pardon to the accomplice under section 306 of the Code of Criminal Procedure.

48)गलत स्थान पर विचारण का क्या प्रभाव होगा?**(M.P. (CJ) 1999)**
(a) स्वयंमेव विदूषित होगा
(b) विदूषित तभी होगा जब न्याय विफल हो
(c) अपराध की गम्भीरता देखनी होगी
(d) उच्च न्यायालय को सन्दर्मित करना होगा

48)What will be the effect of trial at the wrong place?
(a) Will automatically get vitiate
(b) Vitiate will happen only when justice defeat
(c) The graviousness of the offence has to be seen.
(d) Will have to be referred to the High Court

49)दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **468(2)** के तहत, समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद संज्ञान लेने की बाध्यता नहीं

होती है, यदि अपराध..... वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास के रूप में दण्डनीय है।**(Chhattisgarh (CJ) 2016)**

(a) 2
(b) 4
(c) 3
(d) 5

49)Under Section 468(2) of the Code of Criminal Procedure, there is no obligation to take cognizance after the expiry of the time limit, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding ..... years.

(a) 2
(b) 4
(c) 3
(d) 5

50)फौजदारी प्रक्रिया संहिता में निर्धारित सीमा की अवधि निम्नलिखित में से किसके तहत आने वाले अपराधों पर लागू नहीं होता**?(Bihar (CJ) 2016)**

(a) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(b) सीमा-कर अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
(c) विदेश मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)
(d) उपर्युक्त सभी

50)The period of limitation prescribed in the Code of Criminal Procedure does not apply to offences falling under which of the following?
(a) Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)
(b) Customs Act, 1962 (52 of 1962)
(c) Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999)
(d) All of the above

51)कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात धारा **468** के अधीन नहीं करेगा। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है**?(Uttrakhand (CJ) 2019)**
(a) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है।
(b) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है।
(c) दो वर्ष होगा, आर्थिक अपराधों के मामले में।

(d) तीन वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है।

51) No court shall take cognizance of any offence under section 468 after the expiry of the period of limitation under the Code of Criminal Procedure. Which of the following is not correct?

(a) Six months, if the offence is punishable only with fine.

(b) one year, if the offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding one year.

(c) Two years, in case of economic offences.

(d) three years, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding one year but not exceeding three years.

52)यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता, तो यह**-(U.P. A.P.O. 2015)**

(a) असाध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है।

(b) दं.प्र.सं. की धारा 465 (1) के अधीन साध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है।

(c) तात्विक अनियमितता है।
(d) अविधिकता है।

52)If the presiding judge of a court does not sign the judgment, then-
(a) There is an incurable procedural irregularity.
(b) It is a practicable procedural irregularity under Section 465 (1) of the crpc
(c) There is an elemental irregularity.
(d) Illegality.

53). किसी भी दोषपूर्ण न्यायालय **(**क्षेत्राधिकार विहीन**)** में कोई परीक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है तो ऐसा परीक्षण**-(M.P. (CJ) 1989)**
(a) वैधानिक है
(c) अपूर्ण है
(b) अनियमित है
(d) अवैधानिक है

53). If any trial is commenced in any defective court (without jurisdiction), such trial-
(a) Is legal
(c) Is incomplete

(b) Is irregular
(d) Is illegal

54)दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की निम्न किस धारा में वे अनियमितताएं जो विचारण को दूषित करती हैं, बताई गई हैं?**(U.P. A.P.O. 2015)**
(a) धारा 460 में
(b) धारा 461 में
(c) धारा 466 में
(d) धारा 467 में

54) In which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973, those irregularities which vitiate the trial are mentioned?
(a) In section 460
(b) In section 461
(c) In section 466
(d) In section 467

55)सत्र न्यायालय की 'अन्तर्निहित शक्तियां' दी गई है**-(M.P. A.P.O. 1997)**
(a) धारा 481 में

(b) धारा 482 में
(c) धारा 483 में
(d) दण्ड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं

55)The 'inherent powers' of the Sessions Court are given-
(a) In section 481
(b) In section 482
(c) In section 483
(d) Nowhere in the Code of Criminal Procedure

56)दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का, परिसीमा-काल के अवसान के बाद, संज्ञान ले सकता है**?(M.P.A.P.O. 2009 Bihar (CJ) 2009)**
(a) धारा 468
(b) धारा 472
(c) धारा 473
(d) धारा 471

56)Under which section of the Code of Criminal Procedure can any court take cognizance of an offence after the expiry of the period of limitation?

(a) Section 468
(b) Section 472
(c) Section 473
(d) Section 471

57)दण्ड प्रक्रिया संहिता**. 1973** की निम्न धाराओं में से किस धारा में उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है**?(U.P. (CJ) 2016)**
(a) धारा 407 के अंतर्गत
(b) धारा 474 के अंतर्गत
(c) धारा 483 के अंतर्गत
(d) उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण नहीं होता

57) Under which of the following sections of Code of Criminal Procedure 1973, a case can be tried in the High Court?
(a) Under section 407
(b) Under section 474
(c) Under section 483
(d) Trial does not take place before the High Court

RAJASTHALI LAW INSTITUTE

58)किसकी पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **477** के अनुसार नियम बना सकता है?**(Uttarakhand (CJ) 2016 Rai LL.O.2014)**
(a) राज्य सरकार की
(b) केंद्र सरकार की
(c) महान्यायवादी की
(d) केंद्र व राज्य सरकार दोनों की

58)With whose prior approval can the High Court make rules as per Section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973?
(a) State Government
(b) Central Government
(c) Attorney General
(d) Both the central and state governments

59)तीन वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध` संज्ञान के लिये परिसीमा काल होगा**-(U.P. (CJ) 2015**
Chhattisgarh (CJ) 2007
M.P. (CJ) 2005-06)
(a) 90 दिन
(b) एक वर्ष

(c) तीन वर्ष
(d) किसी परिसीमा काल का प्रावधान नहीं है

59) The period of limitation for cognizance of an offence punishable with imprisonment for a term exceeding three years shall be-
(a) 90 days
(b) one year
(c) three years
(d) There is no provision for any limitation period

60)दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** के अधीन निम्न किस धारा में परिसीमा काल के प्रारंभ की तारीख को बताया गया है**?(U.P. (CJ) 2016)**
(a) धारा 467 में
(b) धारा 468 में
(c) धारा 469 में
(d) धारा 470 में
60)Under the Code of Criminal Procedure, 1973, which of the following sections states the date of commencement of the limitation period?
(a) In section 467

(b) In section 468
(c) In section 469
(d) In section 470

61)किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में, नया परिसीमा काल प्रारंभ होता है**-(U.P. (CJ) 2018)**
(a) अपराध की तारीख से।
(b) जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को होती है।
(c) जिस दिन प्रथम बार अपराधी की पहचान का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को होता है।
(d) उस समय प्रत्येक क्षण से जिसके दौरान अपराध चालू रहता है।

61) In the case of a continuing offence, the new period of limitation begins -
(a) From the date of the offence.
(b) The day on which any police officer first becomes known of such offence.
(c) The day on which the identity of the criminal becomes known to the aggrieved person by the offence for the first time.

(d) from every moment of time during which the offence continues.

62)मानहानि के अपराध संज्ञान हेतु धारा **468** दं.प्र.सं. में समय सीमा क्या है**?(M.P.H.J.S. 2016 Uttarakhand (CJ) 2008 M.P. (CJ) 2007 (4) M.P.H.J.S. 2019)**

(a) 6 माह
(b) 1 वर्ष
(c) 3 वर्ष
(d) कोई सीमा नहीं

62) Section 468 Cr.P.C. for cognizance of the offence of defamation. What is the time limit?

(a) 6 months
(b) 1 year
(c) 3 years
(d) No limit

63)दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल प्रारंभ होगा**(M.P. (CJ) (S-II) 2018)**

(a) अपराध के संज्ञान लेने की दिनांक से

(b) अपराध के घटित होने के दिनांक से
(c) शिकायत दर्ज कराने की दिनांक से
(d) इनमें से कोई नहीं

63)Limitation period will start under the Code of Criminal Procedure
(a) From the date of taking cognizance of the offence
(b) From the date of commission of the offence.
(c) From the date of filing the complaint
(d) none of these

64)कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है, यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि**-(Raj. (CJ) 2016)**
(a) विलम्ब को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है
(b) न्यायहित में ऐसा करना आवश्यक है
(c) राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रसंज्ञान लेने हेतु निर्देश दिए गए
(d) (a) एवं (b) दोनों ही दशाओं में

64) Any Court may take cognizance of an offence after the expiry of the period of limitation, if it is satisfied from the facts or circumstances of the case that-

(a) An efforts has been made to explain the delay

(b) It is necessary to do so in the interest of justice

(c) Instructions were given by the State Government to take such recognition.

(d) In both cases (a) and (b)

65)दंड प्रक्रिया संहिता के द्वितीय अनुसूची का कौन-सा प्ररूप 'आरोप' से संबंधित है?**(Uttarakhand (CJ) 2019)**

(a) प्ररूप सं. 31

(b) प्ररूप सं. 32

(c) प्ररूप सं. 33

(d) प्ररूप. सं. 34

65)Which form of the Second Schedule of the Code of Criminal Procedure is related to 'charge'?

(a) Form No. 31

(b) Form no. 32

(c) Form no. 33

(d) Form. No. 34

66). उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** में दी गई है **-(Jharkhand A.P.P. 2018)**
(a) धारा 481
(b) धारा 482
(c) धारा 483
(d) धारा 465

66). The inherent power of the High Court is given in the Code of Criminal Procedure, 1973
(a) Section 481
(b) Section 482
(c) Section 483
(d) Section 465

67)दीना बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है**-(Uttaranchal (CJ) 2005)**
(a) मृत्युदण्ड से
(b) फांसी के द्वारा मृत्युदण्ड देने से
(c) मृत्युदण्ड के निष्पादन में अधिक विलम्ब होने से
(d) हथकड़ी लगाने से

67)The case of Dina vs Union of India is related to-

(a) By death penalty

(b) By giving death penalty by hanging

(c) Due to excessive delay in execution of death sentence

(d) By handcuffing

68)दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का जिसमें वह स्वयं हितबद्ध है, विचारण नहीं करेगा"**?(U.P. (CJ) 2015 Raj. J.L.O. 2014)**

(a) धारा 478 में

(b) धारा 477 में

(c) धारा 479 में

(d) धारा 481 में

68)Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973 states that no

judge or magistrate will try a case in which he himself is interested?

(a) In section 478
(b) In section 477
(c) In section 479
(d) In section 481

69)एक दांडिक कार्यवाही जो शमनीय नहीं है, अभिखंडित की जा सकती है**-(U.P. (CJ) 2018)**

(a) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा
(b) जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा
(c) उच्च न्यायालय द्वारा
(d) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

69)A criminal proceeding which is not compoundable may be quashed -

(a) By Judicial Magistrate of the first class
(b) By the District and Sessions Judge
(c) By the High Court
(d) By the Supreme Court

70)दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** की धारा **482** के अंतर्गत प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन-सा कार्य नहीं कर सकता**?(Raj. A.P.O. 2011 Raj. (JS) 2011)**

(a) न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा देने का

(b) अपने आपको अपील न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकता जब विधायिका ने उसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अधिकृत नहीं किया है

(c) अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने का

(d) उपरोक्त सभी

70)Which of the following cannot be done by a High Court even while exercising the inherent powers granted under Section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973?

(a)Given police custody From judicial custody

(b) Cannot convert itself into a court of appeal when the legislature has not directly or indirectly authorized it

(c) To review its judgement or order.

(d) All of the above

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

Answer key

1-b
2-d
3-b
4-b

5-d
6-b
7-b
8-a
9-c
10-c
11-a
12-c
13-c
14-c
15-d
16-a
17-b
18-b
19-d
20-c
21-c
22-b
23-d
24-c
25-c
26-c
27-b

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

28-d
29-d
30-a
31-b
32-c
33-d
34-b
35-d
36-d
37-c
38-c
39-a
40-b
41-b
42-d
43-a
44-d
45-c
46-a
47-c
48-b
49-c
50-d

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

51-c
52-b
53-d
54-b
55-d
56-c
57-b
58-a
59-d
60-c
61-d
62-c
63-b
64-d
65-b
66-b
67-b
68-c
69-c
70-c

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE

RAJASTHALI
LAW INSTITUTE